Prosecution Service | British Columbia | Crown Counsel Policy Manual

नीति:		
मार्गदर्शक सिद्धांत		
नीति संहिता:	प्रभावी दिनांक:	प्रति-निर्देश:
GUI 1	मई 20, 2022	

अभियोजन के निहित अधिकार

प्रभुत्व-संपन्न को शांति बनाए रखने और अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का संवैधानिक अधिकार और दायित्व है। अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की ज़िम्मेदारी, क्राउन के मुख्य कानून-अधिकारी के तौर पर प्रत्यक्ष और विशेष तौर पर अटॉर्नी जनरल (AG) की होती है। उस हैसियत से, AG को ''राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभावों से स्वतंत्र रहते हुए'', कार्य करते समय "स्वयं को सिद्ध करना" होता है।[1]

अंततः AG प्रांतीय क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी मुकदमों के लिए ज़िम्मेदार होता है और उन्हें इस संवैधानिक भूमिका को स्वतंत्र और न्यायिक ढंग से ज़रूर पूरा करना चाहिए। AG का अभियोजन पक्ष संबंधी कार्य क्राउन काउंसल को सौंपा गया है, जो अपने वैध प्रतिनिधियों के तौर पर AG की ओर से अभियोजन कार्य करते हैं। AG इस कार्य की निगरानी करता है और अभियोजन पक्ष संबंधी सभी निहित अधिकारों के सभी कार्य संपन्न करने के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह रहता है।

अभियोजन पक्ष संबंधी विवेक इस ऐतिहासिक, कानूनी और संवैधानिक संदर्भ से आता है और इसके द्वारा विनियमित होता है।

अभियोजन में स्वतंत्रता

चूंकि अभियोजन के लिए AG को ज़िम्मेदारी सीधे प्रभुत्व-संपन्न से मिलती है, सरकार से नहीं, इसलिए AG को मंत्रिमंडल से स्वतंत्र रहते हुए, इस विवेक का उपयोग ज़रूर करना चाहिए:

> *अटॉर्नी जनरल या उनके प्रतिनिधियों का निर्णय, प्रभुत्व-संपन्न द्वारा उसे दिए गए अधिकार के अंतर्गत सरकार के अन्य प्रावधानों के हस्तक्षेप से मुक्त है। इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा उपयोग किए गए विवेक का अदालतों और कार्यपालिका के अन्य सदस्यों द्वारा पूरा सम्मान किया जाएगा ...*[2]

अभियोगों की निगरानी करते हुए, AG को "सरकार के राजनीतिक दबाव" और अन्य बाहरी निकायों से स्वतंत्र रहते हुए ही कार्य करना चाहिए।[3] "मुकदमा चलाया जाए या बंद किया जाए या नहीं से जुड़े निर्णय सरकार की नीति के मामले नहीं हैं। ये निर्णय पूरी तरह AG के अधिकार में होते हैं, जिन्हें इन उद्देश्यों हेतु एक स्वतंत्र अधिकारी के तौर पर

---

1 Morgan, D "अभियोजन पक्ष की शक्तियों को नियंत्रित करना – न्यायिक समीक्षा, प्रक्रिया का दुरूपयोग और चार्टर की धारा 7" (1986-87) 29 Crim LQ 15 अनुच्छेद 19 में

2 *Krieger v लॉ सोसायटी ऑफ़ अलबर्टा*, 2002 SCC 65 अनुच्छेद 45 में

3 *Miazgav Kvello Estate*, 2009 SCC 51 अनुच्छेद 46 में; *Krieger v लॉ सोसायटी ऑफ़ अलबर्टा*, 2002 SCC 65 अनुच्छेद 30-32 में

स्वीकार किया जाना चाहिए, उनके द्वारा किए गए ऐसे कार्य, कई तरह से एक जज के कार्यों के समान ही होते हैं।"[4] इसलिए AG की स्वतंत्रता "आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता और दक्षता के लिए इतनी मौलिक है कि इसे संवैधानिक तौर पर मज़बूती से स्थापित किया गया है।"[5]

अभियोग चलाने में, क्राउन काउंसल AG के प्रतिनिधियों के तौर पर कार्य करते हैं। उनका अधिकार सीधे तौर पर उन शक्तियों ने तैयार किया है, जो AG के कार्यालय का मूल आधार निर्मित करती हैं। AG की स्वतंत्रता, सहायक डिप्टी अटॉर्नी जनरल (ADAG), BC अभियोजन सेवा (BCPS) के माध्यम से कार्य संपन्न करती है, जो अटॉर्नी जनरल मंत्रालय की आपराधिक न्याय शाखा और क्राउन काउंसल है। क्राउन काउंसल की भूमिका अर्द्ध-न्यायिक है।[6] वे सैक्रेटरी ऑफ़ जस्टिस हैं:

> *इस बात पर अधिक ज़ोर नहीं दिया जा सकता कि आपराधिक अभियोजन का उद्देश्य सज़ा मिलना नहीं है; क्राउन, अपराध के लिए कथित रूप से जिसे प्रासंगिक विश्वसनीय सबूत मानता है, इसे एक जूरी के सामने पेश करना होता है। यह ध्यान रखना काउंसल का कर्तव्य है कि तथ्यों के सभी उपलब्ध कानूनी प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं: यह काम दृढ़ता से किया जाना चाहिए और इसके वैध मज़बूत पक्ष पर ज़ोर देना चाहिए, परंतु यह कार्य निष्पक्षता से ही किया जाना चाहिए। अभियोजक का कार्य, उसे जीतने या हारने की किसी भी धारणा से बाहर रखता है...*[7]

बतौर "सैक्रेटरी ऑफ़ जस्टिस" अभियोजक की भूमिका में तीन प्रमुख घटक शामिल हैं

> *पहला निष्पक्षता वाद है, अर्थात तरफ़दारी वाली भावनाओं या पूर्वाग्रहों से अप्रभावित तथ्यों के साथ निष्पक्षता से निपटने का कर्तव्य। दूसरा अन्य हितों से स्वतंत्रता है, जो अभियोजन पर असर डाल सकते हैं, इसमें पुलिस और बचाव-पक्ष शामिल है। तीसरे का संबंध पहले घटक से है, संदिग्ध या अभियुक्त के प्रति – या तो नकारात्मक या सकारात्मक - दुश्मनी न रखना। क्राउन अटॉर्नी से बिना किसी भेदभाव के कार्य संपन्न करने की उम्मीद की जाती है।*[8]

क्राउन काउंसल को उन तरफ़दारियों और रूढ़ियों को चुनौती देते समय सतर्क रहना चाहिए, जो एक-समान और निष्पक्ष न्याय पाने को हानि पहुंचा सकती हैं। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून को बढ़ावा देने हेतु क्राउन काउंसल की स्वतंत्रता और निरपेक्ष निष्पक्षता महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्राउन काउंसल को न्याय प्रणालियों में शामिल अन्य सहयोगियों की भूमिकाओं का सम्मान करना चाहिए। क्राउन काउंसल को यह बात मान लेनी चाहिए कि एक तटस्थ और निष्पक्ष जज या जूरी के सामने सुनवाई कानून अनुसार की जाएगी और जज या जूरी के अंतिम प्रभाव या साक्ष्य की विश्वसनीयता के उनके अपने व्यक्तिपरक दृष्टिकोण का प्रतिस्थापन करके जज या जूरी की भूमिका पर हावी नहीं होना चाहिए।

पुलिस से स्वतंत्रता

न्याय प्रणाली के भीतर, पुलिस और अभियोजक अपने निर्णय अलग से और एक दूसरे पर प्रभाव डाले बिना और सभी बाहरी प्रभावों से करते हैं। पुलिस और क्राउन काउंसल के बीच संबंध "पारस्परिक स्वतंत्रता" में से एक है, जो "जांच-पड़ताल और अभियोजन, दोनों शक्तियों के दुरूपयोग से सुरक्षा प्रदान करती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि जांच-पड़ताल और अभियोजन दोनों अच्छी तरह और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाते हैं।"[9] क्राउन काउंसल को

4 Ian Scott, "*अटॉर्नी जनरल की भूमिका और अधिकारों का चार्टर*" (1986-87) 29 आपराधिक न्याय त्रैमासिक अनुच्छेद 190 में

5 *Miazga v Kvello Estate,* 2009 SCC अनुच्छेद 46 में; *Krieger v लॉ सोसायटी ऑफ़ अलबर्टा,* 2002 SCC 65

6 *Miazga v Kvello Estate,* 2009 SCC 51 अनुच्छेद 47 में

7 *R v Boucher* (1954), 110 CCC 263 (SCC) प्रति Rand J.

8 *R v Regan,* 2002 SCC 12 प्रति Binnie J. अनुच्छेद 156 में , अन्य बिंदू पर असहमति

9 *Smith v Ontario (अटॉर्नी जनरल),* 2019 ONCA 651 अनुच्छेद 86 में

पुलिस के साथ अपने व्यवहार और आरोपों के आकलन में निष्पक्ष ही रहना चाहिए।

जांचकर्ता और अभियोजक की भूमिका की पारस्परिक स्वतंत्रता की रक्षा करना निष्पक्षता और कानून को बढ़ावा देता है। अपने संबंधित कर्तव्य निभाने में पुलिस और क्राउन काउंसल दोनों का अपना "विवेक है, जिसका किसी भी बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र रहकर ही उपयोग किया जाना चाहिए।"[10]

न तो AG और न ही BCPS को कोई भी जांच करने या जांच करने का आदेश देने का कोई अधिकार है। अपने विवेक के स्वतंत्र उपयोग में यह पुलिस ही है, जो कि अधिकृत है और उसे कथित ग़लत आपराधिक कार्यों की जांच करने और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और निर्णय करना होता है कि आरोप निर्धारण और संभावित अभियोजन हेतु जांच संबंधी फ़ाइल BCPS को भेजनी चाहिए। जांचकर्ता स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं कि उन्हें यह जांच करनी चाहिए या नहीं और जांच कैसे करनी चाहिए, किसकी जांच की जाने चाहिए, कौन से सबूत इकठ्ठे किए जाने हैं और जांच के दौरान कानूनी सलाह लेनी है या नहीं।[11] किसी भी मामले में शामिल होने से पहले, क्राउन काउंसल को जांच एजेंसी से या तो कानूनी सलाह के लिए अनुरोध या क्राउन काउंसल को रिपोर्ट (RCC) मिलनी चाहिए।

स्वतंत्रता और कानून

"कानून" मौलिक न्याय का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसके लिए ज़रूरी है कि "सभी व्यक्ति, संस्थाएं और इकाईयां, सार्वजनिक और निजी ... कानूनों के प्रति जवाबदेह हैं, जिनकी सार्वजनिक तौर घोषणा की जाती है, एक-समान रूप से लागू हैं और स्वतंत्र तौर पर न्याय-निर्णय किया जाता है।"[12] यह ज़रूरी है कि सभी लोग एक-समान रूप से कानून के अधीन हो, और यह मनमाने ढंग से किए जाने वाले भेदभाव पर नकेल कसता है। यह राज्य द्वारा की जाने वाली मनमानी कार्यवाही से बचाता है और इससे एक स्थिर, अपेक्षित और व्यवस्थित समाज को बढ़ावा मिलता है।[13]

कानून बनाए रखने के लिए अभियोजन पक्ष की स्वतंत्रता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। क्राउन काउंसल की स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि वह "किसी मामले में निडर होकर या निष्पक्ष रहकर, किसी अन्य स्रोत के अनुचित दबाव के बिना सही निर्णय ले सकता है, चाहे वह मीडिया, राजनेता, पुलिस, बदले की उम्मीद कर रहा पीड़ित, यहां तक कि गुमराह लोगों द्वारा दी गई राय हो।"[14] इसका उपयोग करने से अभियोजन-स्वतंत्रता का सिद्धांत जनता के विश्वास को बढ़ाता है कि आपराधिक न्याय निष्पक्षता से और पक्षपातपूर्ण राजनीतिक चिंताओं से मुक्त होकर अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा।

क्राउन काउंसल को कानून के अंतर्गत रहते हुए ही कार्य करना चाहिए और अपने विवेक का न्यायसंगत ढंग से, निष्पक्षता से, सद्भाव और उच्चतम नैतिक मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। अभियोजन पक्ष के विवेक के किसी भी प्रयास को राजनीतिक, व्यक्तिगत और निजी विचारों द्वारा प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। क्राउन काउंसल के "निष्पक्षता और स्वतंत्रता के दायित्व ... राज्य-सत्ता के कभी कभार बहुत उत्साही या गुमराह करने के प्रयास के विरूद्ध नागरिक को ज़रूरी सुरक्षा देते हैं।" अदालती स्वतंत्रता के साथ ही क्राउन काउंसल की स्वतंत्रता "हमारी आपराधिक न्याय-प्रणाली के बहुत महत्वपूर्ण नियंत्रण और संतुलन में से एक है।"[15]

क्राउन काउंसल BCPS में अपने पर्यवेक्षकों के प्रति जवाबदेह होते हैं; AG को; अदालत में अपनी रणनीति हेतु या अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए अदालतों के सामने, जहां वह पेश होते हैं; और कानूनी पेशे के मानकों की

10 *R v Beaudry*, 2007 SCC 5 अनुच्छेद 48 में

11 *R v Metropolitan Police Commissioner ex parte Blackburn*, [1968] 1 All ER 763 (CA)

12 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, "संघर्ष और संघर्ष के बाद के समाजों में कानून और संक्रमणकालीन न्याय", S/2004/616 अनुच्छेद 6 में

13 *Reference re Secession of Quebec*, 1998 2 SCR 217 अनुच्छेद 70 में

14 James Hamilton, "*अभियोजन पक्ष की स्वतंत्रता और जवाबदेही*" (Strasbourg, France: ऑनलाइन से पुनः प्राप्त किया गया, मार्च 15, 2011): कानून के माध्यम से लोकतंत्र के लिए यूरोपीय आयोग की कार्यवाही (वेनिस आयोग) "न्यायधीशों और अभियोजकों की स्तंत्रता: परिपेक्ष्य और चुनौतियां"

15 *R v Regan*, 2002 SCC 12, per Binnie J अनुच्छेद 157 में, अन्य बिंदू पर असहमति

अपनी शासन-विधि में प्रांतीय लॉ सोसायटी के प्रति जवाबदेह होते हैं; AG के प्रतिनिधि के तौर पर क्राउन काउंसल अपने विवेक के उपयोग से AG को स्थायी तौर पर बाध्य नहीं कर सकते।[16]

क्राउन काउंसल कानून

क्राउन काउंसल कानून[17] अभियोजन पक्ष की स्वतंत्रता के सिद्धांत को सार्थक प्रभाव देता है। *क्राउन काउंसल* कानून के अंतर्गत BCPS, क्राउन की ओर से, ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, में सभी आपराधिक और नियामक अभियोजन और अपीलों को मंज़ूरी देने और संचालन करने के लिए ज़िम्मेदार है। BCPS का प्रबंध ADAG द्वारा किया जाता है, जिसे *आपराधिक संहिता (Criminal Code)* के उद्देश्यों के लिए AG के वैध डिप्टी के रूप में नामित किया गया है।[18] ADAG क्राउन की ओर से मुकदमों और अपीलों को मंज़ूरी देने और संचालित करने के लिए क्राउन काउंसल, *तदर्थ* कानूनी काउंसल और विशेष अभियोजकों को नामित या नियुक्त करता है।

क्राउन काउंसल कानून, AG के द्वारा BCPS और सरकार के बीच संबंधों को भी नियंत्रित करता है और BCPS को अपने आदेश के उपयोग में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह आवश्यकता अनुसार पारदर्शिता लागू करता है कि विशिष्ट अभियोगों के बारे में AG या डिप्टी अटॉर्नी जनरल (DAG) के किसी भी निर्देशों को लिखित तौर पर वर्णित किया जाए और राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। AG या DAG द्वारा दिए गए किसी नीति निर्देशों को भी लिखित तौर पर वर्णित किया जाना चाहिए और ADAG के विवेक पर राजपत्र में प्रकाशित किया जा सकता है। पारदर्शिता, अनुचित राजनीतिक प्रभाव के आरोपों से बचाती है कि निराधार होने पर भी AG के लिए, सरकार के लिए और लोगों की न्याय की धारणा के लिए महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।[19]

क्राउन काउंसल कानून विशेष अभियोजक नियुक्त करने के अधिकार के साथ ADAG राजनीतिक तौर से संवेदनशील अभियोगों को भी अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाता है। विशेष अभियोजक, BCPS से स्वतंत्र तौर पर और AG के तत्काल पर्यवेक्षी प्राधिकरण के बाहर अभियोजन संबंधी फ़ाइलों पर अपना निर्णय लेते हैं। AG, DAG या ADAG किसी विशेष अभियोजक को विशेष अभियोजक के राजपत्र के भीतर किसी भी मामले के संबंध में निर्देश दे सकता है, लेकिन वह निर्देश लिखित तौर पर और राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।

क्राउन काउंसल कानून BCPS को सार्वजनिक संचार संबंधी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का एक उपाय भी देता है। जब ADAG निर्णय करता है कि हाई-प्रोफ़ाइल मामले में निर्णय संबंधी सार्वजनिक बयान जारी करना जनहित में है, तो BCPS एक स्पष्ट वक्तव्य (सांविधिक व्याख्या) जारी कर सकती है।

नीति का उद्देश्य

कानून के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी अभियोजन आवश्यक हैं। अच्छी तरह से विकसित नीति सबंधी दिशानिर्देशों द्वारा न्याय-प्रणाली को बढ़ाया जा सकता है, कठिन निर्णयों में क्राउन काउंसल की सहायता करते हैं कि उन्हें जनहित को ध्यान में रखते हुए ज़रूर बनाना चाहिए।

क्राउन काउंसल नीति संबंधी नियमावली (''नियमावली ''), क्राउन काउंसल द्वारा अपने विवेक का उपयोग करते समय सामान्य और स्थिति विशेष संबंधी मार्गदर्शन दोनों प्रदान करती है, इसमें मौलिक अभियोजन विचार, जैसे आरोप निर्धारण, वैकल्पिक उपाय, ज़मानत और समाधान चर्चा शामिल हैं। क्राउन काउंसल को न्याय-प्रणाली को निष्पक्ष

16 *R v Nixon*, 2011 SCC 34

17 *क्राउन काउंसल कानून*, RSBC 1996, c.87

18 *क्राउन काउंसल कानून*, RSBC 1996, c.87 section 3(2)

19 *Vogel v Canadian Broadcasting Corp., Bird and Good* [1982], 3 WWR 97 (BCSC); *अभियोजन के विवेक संबंधी आयुक्त स्टीफ़न ओवेन की जांच-रिपोर्ट,* 1990; *Blackmore v British Columbia* (*अटॉर्नी जनरल*), 2009 BCSC 1299

और प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु नियमित तौर पर ये स्वतंत्र और विवेकाधीन निर्णय लेने चाहिएं। जब क्राउन काउंसल इस नियमावली में वर्णित नीतियों के अनुसार सैद्धांतिक निर्णय लेता है, तो परिणाम की परवाह किए बिना BCPS और ADAG उसके निर्णयों का समर्थन करेंगे।

नियमावली एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है। इसका प्रकाशन पारदर्शिता के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। यह इस बात को समझने में मदद करती है कि अभियोजन सेवाएं कैसे दी जाती हैं और अभियोजक व्यक्तिगत मामलों संबंधी जनहित में अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करते हैं।

नियमावली का कोई कानूनी दर्जा नहीं है। यह किसी भी तरह से *आपराधिक कानून (Criminal Code),* कनाडा का *अधिकार तथा स्वतंत्रता का चार्टर (Charter of Rights and Freedoms)* या कोई अन्य लागू कानून किसी भी ढंग से इसका स्थान नहीं लेता और इसका उद्देश्य नागरिकों को कानूनी सलाह देना नहीं है या किसी कानूनी कार्यवाही में कानून में लागू करने योग्य कोई अधिकार बनाना नहीं है।

सैद्धांतिक निर्णय लेना

इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्राउन काउंसल को अपने मौलिक मुद्दों के बारे में निर्णय लेने में सहायता करना है। विशेष नीतियां उपयुक्त जनहित विचार दर्शाती हैं और विवेक का उपयोग करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती हैं। ये नीतियां अभियोजन पक्ष के विवेक की हद और उचित अभ्यास का प्रबंध करने वाले न्यायशास्त्र को भी दर्शाती हैं।

जब भी उपयुक्त हो, क्राउन काउंसल को और भी सलाह लेनी चाहिए। यहां तक कि बहुत ही सीनियर क्राउन काउंसल, सहयोगियों की काउंसल की सलाह लेगा और नीति द्वारा अपेक्षित होने पर पर्यवेक्षकों की स्वीकृति लेगा। कानून और न्यायशास्त्र, प्रौद्योगिकी, अदालत के नियमों और प्रक्रियाओं में विकास का मतलब है कि कानूनी परिदृश्य हमेशा बदल रहा है। प्रैक्टिस या प्रक्रिया के अनजान क्षेत्रों में नीति का उल्लेख करना विशेष तौर पर सहायक हो सकता है।

यह नीति, AG के लिए जवाबदेही और अभियोजन पक्ष के विवेक का तर्कयुक्त और सैद्धांतिक उपयोग करने का अवसर देती है। अंततः इसका लक्ष्य न्याय-प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ाना है।

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष के विवेक के उचित उपयोग की न तो आवश्यकता है न ही प्रत्येक निर्णय के लिए यह नीति का कठोरता से उपयोग करने का समर्थन करता है। नीति मार्गदर्शन करती है, लेकिन यह प्रत्येक मामले में परिणाम के लिए दबाव नहीं डाल सकती और न ही ऐसा करने चाहिए। क्राउन काउंसल को प्रत्येक मामले की असाधारण परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लेने पड़ते हैं।

नीतियों में विशेष जनहित कारकों पर विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है या इस बात की ज़रूरत है कि BCPS के वरिष्ठ सदस्यों से परामर्श किया जाए या कुछ स्थितियों में स्वीकृति दी जाए। हालांकि, नीति क्राउन काउंसल के अभियोजन पक्ष संबंधी विवेक का उपयोग करने को पूरी तरह बाधित नहीं करेगी। इस कारण से, नीतियों में विरले ही अनिवार्य निर्देश होते हैं। जहां उन्हें ऐसा करना पड़ता है, वे आमतौर पर असाधारण कारकों पर विचार करने के लिए जगह छोड़ देते है। यदि उनके अभियोग पक्ष का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस नीति से हटने के लिए क्राउन काउंसल, ADAG की सहमति ले सकता है, इसलिए क्राउन काउंसल केवल न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करता है।

ग़लत फैसलों की रोकथाम

BCPS मानती है कि आपराधिक न्याय-प्रणाली में स्पष्ट तौर पर और प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपायों के बावजूद ग़लत सज़ा हो सकती हैं। सुरक्षा उपायों में निर्दोष होने का अनुमान, क्राउन पर सबूत एकत्र करने का बहुत अधिक बोझ और पुलिस, क्राउन काउंसल और अदालतों की स्वतंत्रता शामिल है। *अधिकार तथा स्वतंत्रता का चार्टर (Charter of*

Rights and Freedoms) की गारंटी, जैसे कि क्राउन द्वारा किसी अभियुक्त के पूरे ख़ुलासे का अधिकार आगे चलकर व्यक्तियों को ग़लत तरीके से दोषी ठहराए जाने से रोकता है।

हालांकि, क्राउन काउंसल को ग़लत सज़ा में योगदान देने वाले कारकों से हमेशा सचेत रहना चाहिए, उसे किसी उपयुक्त मामले में मुकदमा चलाने या उसकी वैध शक्ति के लिए दबाव डालने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। क्राउन काउंसल दृढ़, लेकिन निष्पक्ष अभियोजन चलाकर जनहित की रक्षा करते है और उसे बढ़ावा देते हैं।

ग़लत सज़ा के प्रमुख कारण

खोज दर्शाती है कि विभिन्न संभव कारकों के कारण गलत धारणा बन सकती है, या तो अकेले काम करना चाहिए या मिल जुल कर। प्रत्येक अभियोजन का प्रबंध करने में, क्राउन काउंसल को इन कारकों का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ग़लत सज़ा के प्रमुख कारणों में समस्याग्रस्त सबूत शामिल हैं, जैसे:

- ग़लत चश्मदीद की पहचान करना: नेकनीयत, ईमानदार और विश्वसनीय चश्मदीद गवाह भी ग़लत हो सकते हैं
- विशेषज्ञ के दोषपूर्ण सबूत और फ़ोरैंसिक: भ्रष्ट, सबूत तैयार किया गया या विशेषज्ञ के अप्रमाणित सबूत, वैज्ञानिक शब्दावली वाला और भाषा और अविश्वसनीय तथ्यों या खंडित विज्ञान पर आधारित
- झूठे बयान और जुर्म कबूल करना: कुछ अभियुक्त व्यक्ति तथ्यात्मक तौर पर निर्दोष होने के बावजूद हामी भरते हैं या जुर्म कबूल करते है
- हिरासत में बेईमान मुखबिर गवाह: उनके साक्ष्य पर भरोसा करने से असाधारण जोखिम होता है, जिसका विशेष तौर पर *हिरासत में बेईमान मुखबिर गवाह (In-Custody Informer Witnesses)* (INC 1) नीति में समाधान किया गया है

क्राउन काउंसल की "विचार-संकीर्णता", किसी मामले के एक विशेष सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करने और उस सिद्धांत[20] के विरूद्ध काम करने वाले सबूत रद्द करने या कम आंकने की प्रवृत्ति को भी ग़लत सज़ा देने में एक योगदान डालने वाले कारण के तौर पर पहचाना गया है। पुलिस से स्वतंत्रता, साक्ष्य-निर्धारण में निष्पक्षता, सैद्धांतिक निर्णय करना, जैसा कि BCPS नीति द्वारा सूचित और निर्देशित किया गया है, क्राउन काउंसल को इस विचार-संकीर्णता से बचने में मदद मिलती है। इसलिए, जब इसे उचित ढंग से पूरा किया जाता है, तो क्राउन काउंसल ग़लत सज़ा देने से बच सकता है।

किसी अभियुक्त के लिंग, जाति, उम्र या सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना भी न्याय हानि होती है। फिर भी, क्राउन काउंसल को प्रणालीगत पक्षपात, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं, जो असमानता बढ़ा सकती हैं और इस कारण से अनुचित मुकदमे हो सकते हैं और ग़लत सज़ा भी हो सकती है, का समाधान करने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

ग़लत सज़ा की रोकथाम के लिए कार्य करने के अलावा, अभियोजन समाप्त होने के बाद भी क्राउन काउंसल को सतर्क रहना चाहिए। यदि यह निष्कर्ष निकालने के लिए उचित आधार है कि न्याय हानि हो सकती है, तो BCPS मामले के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

मूल व्यक्ति

20 अभियोजन रिपोर्ट के प्रमुख, *मासूमियत दांव पर: कनाडा में ग़लत आरोप-निर्धारण रोकने हेतु निरंतर सतर्कता की आवश्यकता,* www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/is-ip/ch2.html, अभियोजन समिति के FPT प्रमुख, 2018.

कई सरकारी आयोगों और रिपोर्टों के साथ ही कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में यह बात मानी गई है कि मूल व्यक्तियों (फ़र्स्ट नेशन, मैटिस और इन्यूट) द्वारा बर्दाश्त किए गए भेदभाव, चाहे वे स्पष्ट तौर पर नस्लवादी दृष्टिकोण या सांस्कृतिक तौर पर अनुचित प्रथाओं के कारण हुए हों, जबकि आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी भागों में भी इनका विस्तार हुआ है।

कनाडा में उपनिवेशवाद, विस्थापन और आवासीय विद्यालयों के इतिहास ने निम्न शैक्षणिक उपलब्धि, कम आय, उच्च बेरोज़गारी, मादक द्रव्यों के सेवन और आत्महत्या की उच्च दर और मूल व्यक्तियों की कैद के उच्च स्तर को दर्शाया है।[21]

मूल व्यक्तियों की उत्पीड़न दर, विशेष तौर पर मूल महिलाओं और लड़कियों की उत्पीड़न दर भी ग़ैर- मूल व्यक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक है।[22]

कनाडा में मूल व्यक्तियों के लिए उपनिवेशवाद के निरंतर परिणाम, पीड़ित या संभावित अभियुक्त के तौर पर मूल व्यक्ति से संबंधित किसी भी आरोप निर्धारण के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करते हैं। इन परिणामों को "मूल लोगों को प्रभावित करने वाले असाधारण प्रणालीगत और पृष्ठभूमि संबंधी कारकों के साथ ही उनके मौलिक तौर पर विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों और वैश्विक विचारों को ध्यान में रखकर उपाय ज़रूर करने चाहिए।"[23]

खोज दर्शाती है कि विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक कारणों से मूल व्यक्तियों को गलत तरीके से सजा दी जाती है।[24] आपराधिक न्याय-प्रक्रिया के प्रत्येक पड़ाव में, क्राउन काउंसल को उन चुनौतियों पर विचार करना चाहिए, जिनका मूल व्यक्तियों को न्याय-प्रणाली के साथ बातचीत करते समय सामना करना पड़ता है और यह भी कि ये चुनौतियां ग़लत सज़ा का रूप कैसे ले सकती हैं।[25]

वाक्यांशों का अर्थ

नियमावली में दिया गया "मूल" शब्द कनाडा के फ़र्स्ट नेशन, मैटिस और इन्यूट लोगों को संदर्भित करता है। इसका उपयोग "आदिवासी" शब्द के स्थान पर किया जाता है, इसका उपयोग *आपराधिक संहिता (Criminal Code)* सहित विभिन्न विधानों में किया जाता है और यह *मूल लोगों के कानून के अधिकारों संबंधी BC घोषणापत्र (*BC *Declaration of the Rights of Indigenous Peoples Act)*, SBC 2019, c. 44. के अनुरूप है।

इसके अलावा, नियमावली में दिए गए "चाहिए" और "अवश्य/ज़रूर/ही" शब्दों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है:

> "क्राउन काउंसल को चाहिए" का अर्थ है कि क्राउन काउंसल आमतौर पर नीति संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे, जब तक कि वे न्याय के हितों का निर्णय नहीं करते, नीति संबंधी दिशानिर्देश के साथ असंगत निर्णय की आवश्यकता होती है
>
> "*क्राउन काउंसल कानून (Crown Counsel Act)* की धारा 4(3) के अंतर्गत सहायक डिप्टी अटॉर्नी जनरल (ADAG) के निर्देशानुसार "क्राउन काउंसल का गठन अवश्य करना चाहिए"

21 *R v Ipeelee*, 2012 SCC 13

22 *कनाडा में स्वदेशी लोगों का उत्पीड़न, 2014*, सांख्यिकी कनाडा, 2016

23 *Ewert v Canada*, 2018 SCC 30 अनुच्छेद 57 और 58 में; *R v Barton*, 2019 SCC 33 अनुच्छेद 198-200 में

24 Kent Roach, "*ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में स्वदेशी लोगों की ग़लत धारणा*" फ़्लैंडर्स लॉ जरनल 17, 2015 अनुच्छेद 224 में; Amanda Carling, *बहुत अधिक स्वदेशी प्रतिनिधित्व कम करने का तरीका : ग़लत दोषी- याचिका को ग़लत ढंग से रोकना* , 2017 64 CLQ 415

25 *मासूमियत दांव पर: कनाडा में ग़लत आरोप-निर्धारण रोकने हेतु निरंतर सतर्कता की आवश्यकता,* c 10, s 3: अभियोजन समिति के FPT प्रमुख, 2018 (www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/is-ip/ch10.html#ch10_3)